

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 236/2016/225 आरटीए

1. गुलाम मोहम्मद पुत्र चांदा जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
2. ज्यान मोहम्मद पुत्र चान्दा जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
3. इकबाल खां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
4. नवाब खां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
5. असगर खां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।
6. मुन्शीखां पुत्र सदीक खां जाति सिक्क निवासी डोबी बास भादरा तहसील भादरा।

—अपीलान्ट

—: बनाम :-

1. लिलूखां पुत्र जुमिया पुत्री चान्दा पत्नि मागुखां जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।

—असल रेस्पोंडेंट

2. पप्पू खां पुत्र सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
3. बानो पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
4. नजमा पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
5. धापा पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
6. उलफत पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
7. महरून पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।
8. नवाबखां पि. सदीकखां पुत्र चान्दा जाति सिक्का मुसलमान वार्ड नं. 7 भादरा तहसील भादरा।

—तरतीबी रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.11.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 113/13 अनवानी लीलूखां बनाम गुलाम मोहम्मद आदि उपस्थित :-

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पों सं. 1

निर्णय

दिनांक -30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पों सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि में अपने नाना चान्दा का 1/2 हिस्सा बताया है तथा चान्दा के वारिसान गुलाम मोहम्मद ज्यान मोहम्मद, सदीक, जुमिया को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त होना बताया है तथा अपनी माता जुमिया के फौत होने के बाद चान्दा के 1/2 भाग में 1/4 भाग व वाद भूमि उसका 1/8 भाग बताया है जबकि उक्त तथ्य को साबित करने हेतु रेस्पों ने चान्दा का वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया बिना दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पों सं. 1 की माता जुमिया को चान्दा की पुत्री होना अधीनस्थ न्यायालय ने कतई विधि विरुद्ध माना है जबकि जुमिया चान्दा की पुत्री नहीं है। वास्तविकता यह है कि चान्दा की शादी जब सुभानी से हुई थी तो सुभानी की चान्दा से पहले शादी बीकानेर हुई थी और बीकानेर में सुभानी के उक्त लड़की जुमिया पैदा हुई थी लेकिन सुभानी का बीकानेर जो निकाल हुआ था उससे तालाक हो जाने के पश्चात सुभानी ने दूसरी शादी चान्दा से की थी। जुमिया सुभानी व उसके चान्दा से पूर्व पति से उत्पन्न संतान है। इस प्रकार चान्दा की 1/2 हिस्सा भूमि में जुमिया का कोई हक व हिस्सा नहीं है।
4. जुमिया अगर चान्दा की पुत्री होती तो जुमिया का राशन कार्ड, वोट व अन्य दस्तावेज चान्दा के साथ होते जुमिया कभी भी चान्दा के साथ राशनकार्ड या वोट में ना नहीं है। जुमिया का राशनकार्ड व वोट आदि सरदारशहर में ही लेकिन जुमिया की शादी मांगुखां के साथ होने के बाद जुमिया का वोट व राशन कार्ड मांगुखां के साथ है। जब प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा जुमिया को चान्दा की पुत्री नहीं बताया तथा रेस्पों की उपरोक्त तथ्यों का जवाब प्रार्थना पत्र/जवाबदावा व बहस, शपथ पत्रों में खण्डन किया है तो विचारण न्यायालय को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय पारित कतई विधि की अवहेलना किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी के समर्थन में आरआरटी 2015(1) पेज 633, आरआरटी 2015(1) पेज 560, आरबीजे 2009 पेज 835, आरआरटी 2007(1) पेज 723 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि सिविल न्यायालय प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 9 अधिकारिता घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद उतराधिकारिता का प्रश्न—उतराधिकारिता के प्रश्न को निर्णित करने हेतु केवल सिविल न्यायालय सक्षम है लेकिन राजस्व न्यायालय केवल नामान्तरकरण की प्रविष्टि की वैद्यता अथवा अवैद्यता को निर्णित कर सकता है। अपीलांटस भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जो रेस्पों सं. 1 के नाना एवं अपीलांटस के पिता चान्दा के नाम दर्ज है। रेस्पों सं. 1 जुमिया का पुत्र है और जुमिया चान्दा की पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चान्दा के नाम दर्ज भूमि 1/2 हिस्सा में जुमिया के 1/4 हिस्सा निहित है उक्त हिस्सा की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह उल्लेखित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है कि रेस्पों सं. 1/प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है तब वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि जुमिया चान्दा की पुत्री है इसके संबंध में रेस्पों सं.1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तो रेस्पों सं. 1 ने जुमिया को चान्दा की पुत्री होना अंकित किया है और जुमिया का पुत्र रेस्पों सं. 1 होना अंकित किया है। अधिवक्ता रेस्पों ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 330, आरआरटी 2017 (1) पेज 491, आरआरडी 2010 पेज 96, आरआरडी 2009 पेज 17 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आरआरटी 2017(1) पेज 335 के अनुसरण में हमारे देश में व्यक्ति को पुरुष या महिला साबित करने के लिए सक्षम न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को सन्तान होने या न होने बाबत डिक्री की आवश्यकता है। यह तथ्य तो प्रोबेट उतराधिकार उपयुक्त वाद वाद में ही तय हो सकते हैं कि अमुख व्यक्ति किसी मृतक का पुत्र/पुत्री है अथवा नहीं, अलग से किसी व्यक्ति को अमुख व्यक्ति का पुत्र/पुत्री साबित करने के लिए किसी न्यायालय की डिक्री प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, यह तो विचारण न्यायालय को ही वाद में स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि क्या वादी का वाद कल्याण की पुत्री (अमुख व्यक्ति) होने या नहीं होने के कारण पोषनीय है अथवा नहीं। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।
6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि “ प्रार्थी का वादभूमि में कोई हक व हिस्सा बनता है या नहीं, इसका निर्णय मूल वाद में होना है जिसमें अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूर्णाय क्षति नहीं हो रही

है।" विवादित भूमि अपीलांटस के पिता एवं रेस्पों. सं. 1 के नाना चान्दा के नाम से दर्ज है जब तक यह तय नहीं हो जाता कि विवादित भूमि में रेस्पों सं. 1/प्रार्थी का हक व हिस्सा है या नहीं, तब तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनायी रखी जानी आवश्यक है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रार्थना पत्र रेस्पों स्वीकार किया गया है। उक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। ऐसी स्थिति अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जानी न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़